भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-97

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

झारखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षा

***97. श्री दुलू महतो:**

श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों मं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है;
(ख) सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) झारखंड के धनबाद जिले और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बच्चों की शिक्षा पर सामाजिक-आर्थिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है;
(घ) सरकार द्वारा झारखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(ड.) क्या झारखंड में सरकारी और निजी विद्यालयों की शिक्षा के स्तर में कोई अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

झारखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री दुलू महतो और श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 10.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारत सरकार समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रावधान झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के समक्ष आने वाली पलायन, पहुंच जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता की जानी है।

यूडीआईएसई+ वर्ष 2023-24 के अनुसार, झारखंड में स्कूलों की कुल संख्या 44,475 है, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कुल संख्या 40,452 (90.9%) है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 57,83,641 है, जिनमें से लड़कियों की कुल संख्या 28,36,228 है जो 49.03% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत शिक्षकों की कुल संख्या 1,63,228 है, जिनमें से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 1,08,059 है जो 66.2% है।

(ख): केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों को योजना के मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये प्रशिक्षण संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

समग्र शिक्षा के तहत डीआईईटी को सुदृढ़ करने और उन्हें उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, सरकार ने 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 125 डीआईईटी के उन्नयन के लिए 92,320.18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। निष्ठा को अब सभी स्तर के शिक्षकों: आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकज्ञान के लिए प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक स्तर के शिक्षक तथा मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

झारखंड राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शिक्षकों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करने और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वर्ष 2022 में 96,700 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों और वर्ष 2023 में 13,000 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) आयोजित किया गया था। झारखंड राज्य सरकार ने जे-गुरुजी ऐप विकसित किया है, जो पाठ्यक्रम के साथ सामग्री का मानचित्रण करता है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक आवश्यकता विश्लेषण किया है। इसके आधार पर, विषय-वस्तु विकसित की जाती है, और विषय विशेषज्ञों द्वारा एक प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रभारी द्वारा निरंतर ऑफ़लाइन निगरानी भी की जाती है।

(ग): झारखंड के धनबाद जिले में मुख्य आर्थिक गतिविधि कोयला खनन है, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में मुख्य रूप से कृषि है। धनबाद और रायपुर जिलों में स्कूल शिक्षा में सामाजिक-आर्थिक कारकों पर ध्यान देने के लिए, सरकार ने पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। यूडीआईएसई+ 2023-24 के अनुसार, झारखंड के धनबाद जिले में स्कूलों की संख्या 2,450 स्कूल है। इसके अलावा धनबाद जिले में 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 3 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 4,64,810 है, जिनमें लड़कियों की संख्या 2,21,375 (47.6%) है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या 15,178 है। प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल छोड़ने की दर 0, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8.2 और माध्यमिक विद्यालयों में 20.1 है। लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर क्रमशः 0, 7.8 और 21.1 है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 2,415 स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 5,39,907 है, जिनमें से लड़कियों की संख्या 2,68,008 (49.63%) है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या 23,756 है। प्राथमिक विद्यालय में स्कूल छोड़ने की दर 0, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2.1 और माध्यमिक विद्यालय में 14.5 है। लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर क्रमशः 0, 0.9 और 10.2 है।

(घ): सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

(i) शिक्षा तक बहुविध पहुँच को सक्षम करने के लिए पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल। पीएम ईविद्या के अंतर्गत प्रमुख पहल इस प्रकार हैं: -

- गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री उपलब्ध कराने के लिए दीक्षा पोर्टल
- बिना कनेक्टिविटी या सीमित कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए 200 पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनल। स्थानीय भाषाओं में विकसित सामग्री के प्रावधान को सक्षम करने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ को पांच-पांच चैनल आवंटित किए गए हैं।
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग।
- दृष्टि एवं श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेजी) और भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) पर आधारित विशेष ई-सामग्री (टॉकिंग बुक्स) विकसित की गई।
- एनसीईआरटी/एनआईओएस के यूट्यूब और डीटीएच चैनल।

(ii) केन्द्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक अनुमोदित आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का वास्तविक और वित्तीय ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	**आईसीटी प्रयोगशालाओं की संख्या (वर्ष** 2005-06 **से)**	**राशि (रुपए लाख** में)	**स्मार्ट कक्षाओं की संख्या** (**वर्ष** 2020-21 **से)**	**राशि (रुपए लाख में)**
छत्तीसगढ़	3,777	13,559.8	10,439	24,921.6
झारखंड	5,322	31,106.3	1,319	3,184.22

स्रोत: प्रबंध

** स्मार्ट क्लासरूम को वित्त वर्ष 2020-21 से एक घटक के रूप में जोड़ा गया*

(ड): यूडीआईएसई+ वर्ष 2023-24 के अनुसार, झारखंड में 71.8% बच्चे सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि 28.2% बच्चे निजी/अन्य प्रबंधन स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, एनईपी 2020 के अनुसार, झारखंड में सरकार द्वारा पीएम श्री स्कूल, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालय जैसी कई पहल की गई हैं।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, 2021 के अनुसार अधिगम परिणाम https://nas.gov.in/report-card/nas-2021 पर उपलब्ध हैं।

*****